© Volume 2, Issue 10, October 2026 | JATIR
e-ISSN: 2839-5786, p-ISSN: 3139-8464

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्वाड (QUAD) की भूमिका और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ

डॉ प्रवीर चन्द्र दुबे

सहायक प्राध्यापक, यमुना प्रसाद शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरमौर जिला रीवा (म प्र.) 486448

***सारांश:-*प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से २१वीं सदी की वैश्विक महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के मुख्य केंद्र के रूप में उभरने वाले हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जारी रणनीतिक संघर्षों का गहन विश्लेषण करना है। विशेष रूप से, यह शोध संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बढ़ते भू-राजनीतिक द्वंद्व, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड - QUAD) के रणनीतिक विकासक्रम और इसके प्रभाव का परीक्षण करता है[1]। इस अध्ययन के सैद्धांतिक आधार के रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नव-यथार्थवादी और नव-आक्रामक यथार्थवादी सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है[2]। शोध से प्राप्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) और 'वैश्विक सुरक्षा पहल' (GSI) जैसी विस्तारवादी नीतियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक गंभीर 'सुरक्षा दुविधा' उत्पन्न कर दी है[2]। इसके उत्तर में क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) का पुनरुद्धार क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हुआ है[6]। अंत में, यह पत्र ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा अपनाई जा रही 'ग्रे-जोन' रणनीतियों से उत्पन्न होने वाली समकालीन सुरक्षा चुनौतियों और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के समक्ष चुनौतियों का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।**

***मुख्य शब्द:* हिंद-प्रशांत, क्वाड (QUAD), भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, नव-यथार्थवाद, समुद्री सुरक्षा, ग्रे-जोन रणनीति, रणनीतिक स्वायत्तता।**

I. भूमिका

समकालीन वैश्विक परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक संक्रमण एशिया-प्रशांत क्षेत्र से स्थानांतरित होकर हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) के रूप में आकार ले रहा है[1]। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद स्थापित अमेरिकी एकध्रुवीय वर्चस्व को अब चीन के तीव्र आर्थिक और सैन्य आधुनिकीकरण से गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है[1]। इस शक्ति संक्रमण को यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत 'थ्यूसीडाइड्स ट्रैप' के रूप में समझा जा रहा है, जिसमें स्थापित और उभरती महाशक्ति के बीच का द्वंद्व अपरिहार्य हो जाता है[1]। हिंद-प्रशांत क्षेत्र केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार मार्गों की जीवन रेखा और तकनीकी व सैन्य आधिपत्य का प्राथमिक मंच है[1]। इस नाजुक भू-राजनीतिक वातावरण में नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने और सुरक्षा वास्तुकला को संतुलित करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (क्वाड) को पुनर्जीवित किया है[7]।

भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र का रणनीतिक विस्तार हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर के मुहाने तक फैला हुआ है[12]। शिंजो आबे ने २००७ में नई दिल्ली में भारतीय संसद को संबोधित करते हुए "दो सागरों के मिलन" का विचार प्रस्तुत किया था, जिसने इस भू-राजनीतिक अवधारणा को जन्म

दिया[4]। आर्थिक रूप से, इस क्षेत्र का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि केवल क्वाड सदस्य देश ही वैश्विक आबादी के २४ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में ३५ प्रतिशत और वैश्विक व्यापार में १८ प्रतिशत का योगदान है[12]। अतः इस क्षेत्र की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता वैश्विक स्थिरता के लिए अपरिहार्य है[14]।

II. शोध-समस्या

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय सुरक्षा वास्तुकला अत्यंत खंडित और अस्थिर है[1]। चीन द्वारा अपनी ऐतिहासिक संप्रभुता के दावों को जबरन थोपने, दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण और ताइवान जलडमरूमध्य में सैन्य गतिविधियों को तेज करने से क्षेत्रीय राज्यों की संप्रभुता संकट में पड़ गई है[8]। चीन की इस आक्रामक नीति और अमेरिका की "एशिया पुनर्संतुलन" रणनीति के कारण इस क्षेत्र में तीव्र सैन्यीकरण और सुरक्षा दुविधा उत्पन्न हो गई है, जिससे छोटे और मध्यम दर्जे के देशों को कूटनीतिक रूप से 'हेजिंग' करने के लिए विवश होना पड़ रहा है[2]। मुख्य शोध समस्या यह है कि क्या क्वाड (QUAD) जैसी अनौपचारिक और लचीली सुरक्षा व्यवस्थाएं, जो नाटो (NATO) की तरह किसी सामूहिक सैन्य रक्षा संधि से बंधी नहीं हैं, चीन की बहुआयामी सैन्य आक्रामकता, भू-आर्थिक आधिपत्य और ग्रे-जोन रणनीति को संतुलित करने में एक स्थायी क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना स्थापित करने में सक्षम हैं[8]?

III. शोध-उद्देश्य

१. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका-चीन के बीच जारी भू-राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के सुरक्षा प्रभावों का विश्लेषण करना[1]।

२. क्वाड (QUAD) के उद्भव, इसके ऐतिहासिक विलोपन और पुनरुद्धार की कूटनीतिक कड़ियों का परीक्षण करना[7]। ३. दक्षिण चीन सागर और ताइवान में चीन की 'ग्रे-जोन' रणनीति तथा सुरक्षा उल्लंघनों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना[8]। ४. भारत की सुरक्षा रणनीति, नौसैनिक बजटीय आवंटन, सीमा बुनियादी ढांचे और इसकी 'रणनीतिक स्वायत्तता' के अंतर्विरोधों का विश्लेषण करना[10]।

IV. शोध-प्रश्न

१. अमेरिका और चीन की भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा वास्तुकला को किस प्रकार पुनर्गठित किया है[1]?

२. एक अनौपचारिक राजनयिक मंच के रूप में क्वाड किस सीमा तक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखने और चीनी आधिपत्य का मुकाबला करने में सफल रहा है[7]?

३. ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन की ग्रे-जोन गतिविधियां स्थापित समुद्री कानूनों (UNCLOS) के समक्ष क्या चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं[8]?

४. भारत कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका के साथ बढ़ते सामरिक झुकाव और अपनी पारंपरिक गुटनिरपेक्ष छवि व क्षेत्रीय संप्रभुता संबंधी प्राथमिकताओं के बीच कैसे समन्वय कर रहा है[23]?

V. साहित्य समीक्षा

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा वास्तुकला पर अकादमिक विमर्श मुख्य रूप से शक्ति संतुलन और संरेखण कूटनीति के इर्द-गिर्द घूमता है। सी. राजा मोहन ने अपनी पुस्तक 'समुद्र मंथन' में तर्क दिया है कि चीन और भारत के बीच का पारंपरिक भू-क्षेत्रीय द्वंद्व अब समुद्री डोमेन में स्थानांतरित हो चुका है, जिससे

हिंद-प्रशांत एक नया रणनीतिक युद्धक्षेत्र बन गया है[26]। मोहन का विचार है कि चीन और भारत के बीच सैन्य व आर्थिक विषमता इतनी बढ़ चुकी है कि भारत को क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका और जापान जैसे बाह्य देशों के साथ कूटनीतिक सहयोग का विस्तार करना ही होगा[24]।

राजेश राजगोपालन ने भारत की सुरक्षा रणनीतियों का विश्लेषण करते हुए इसे पूर्व में "टालने वाला संतुलन" (Evasive Balancing) करार दिया था, जिसमें भारत चीन की आक्रामकता को सीधे चुनौती देने से बचता था[22]। हालांकि, राजगोपालन और हालिया शोधकर्ताओं का मानना है कि गलवान घाटी (२०२०) के सैन्य गतिरोध के बाद भारत ने इस नीति को त्यागकर "क्षेत्रीय संतुलन" (Zone Balancing) की ओर कदम बढ़ाया है, जो क्वाड के भीतर बढ़ते कूटनीतिक और नौसैनिक जुड़ाव से स्पष्ट होता है[21]।

हर्ष वी. पंत के अनुसार, क्वाड का उदय केवल चीन के सैन्य नियंत्रण (containment) तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हिंद-प्रशांत में वैक्सीन कूटनीति, लचीली आपूर्ति शृंखला, बुनियादी ढांचे के विकास और महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे गैर-सैन्य सार्वजनिक सामानों को प्रदान करने वाले एक विस्तृत कूटनीतिक मंच के रूप में विकसित हुआ है[12]। पंत का मानना है कि भारत की कूटनीति अब "गैर-संरेखण" से हटकर "साझेदारियों के नए युग" में प्रवेश कर चुकी है, जहां रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रिय बहु-पक्षीय संरेखण है[10]।

ब्रायन फोंग ने अपने शोध में "नव-आक्रामक यथार्थवाद" (Neo-offensive realism) के वैचारिक ढांचे का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट किया है कि कैसे अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता में ताइवान और दक्षिण चीन सागर सबसे संवेदनशील भू-राजनीतिक दरारें हैं, जो किसी भी क्षण बड़े सैन्य टकराव में बदल सकती हैं[3]।

VI. सैद्धांतिक आधार

प्रस्तुत शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मुख्य सिद्धांत 'नव-यथार्थवाद' (Neorealism) और 'नव-आक्रामक यथार्थवाद' को अपने वैचारिक आधार के रूप में स्वीकार करता है[2]। केनेथ वॉल्ट्ज द्वारा प्रतिपादित नव-यथार्थवाद के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक प्रकृति के कारण प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्व-सहायता और शक्ति के संतुलन पर निर्भर करता है[2]। अराजकता की स्थिति में राज्यों के पास कोई केंद्रीय नियंत्रक निकाय नहीं होता, जिसके कारण 'सुरक्षा दुविधा' का जन्म होता है[5]। इस दुविधा में एक राज्य द्वारा उठाए गए सुरक्षात्मक कदम (जैसे सैन्य आधुनिकीकरण) दूसरे राज्य द्वारा आक्रामक तैयारी के रूप में देखे जाते हैं[5]।

इसके अतिरिक्त, नव-आक्रामक यथार्थवाद यह मानता है कि उभरती हुई महाशक्तियां अपनी शक्ति और प्रभाव को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं ताकि वे क्षेत्रीय आधिपत्य स्थापित कर सकें[3]। चीन की इस आक्रामक आधिपत्यकारी नीति को संतुलित करने के लिए अमेरिका एक "अपतटीय संतुलनकर्ता" की भूमिका निभा रहा है और अपने सहयोगियों को एकीकृत कर चीन के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास कर रहा है, जिसे क्वाड के रूप में देखा जा सकता है[3]।

VII. शोध-विधि

इस शोध पत्र में गुणात्मक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (qualitative analytical approach) को अपनाया गया है[31]। शोध की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए यह प्राथमिक दस्तावेजों (जैसे क्वाड संयुक्त वक्तव्य, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों) और उच्च श्रेणी के द्वितीयक स्रोतों (जैसे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस, जादवपुर जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की शोध रिपोर्टें) के तुलनात्मक विश्लेषण को आधारित माना है[3]। इस अध्ययन में सैन्य और बजटीय डेटा के विश्लेषण के साथ-साथ ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर में हाल की सैन्य गतिविधियों का केस-स्टडी विश्लेषण शामिल है, जो समकालीन भू-राजनीतिक परिवर्तनों को समझने के लिए एक ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है[3]।

VIII. विश्लेषण / व्याख्या

8.1. अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का बहुआयामी स्वरूप

हिंद-प्रशांत क्षेत्र वर्तमान में वैश्विक महाशक्ति प्रतिस्पर्धा की धुरी बन चुका है[1]। संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य प्रधानता और "मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत" (FOIP) की अवधारणा के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित उदारवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है[1]। इसके विपरीत, चीन इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है और अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति को अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में चित्रित करता है[1]।

क्र	सामरिक आयाम	संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) की नीति	चीन जनवादी गणराज्य (पीआरसी) की नीति
1	सुरक्षा गठबंधन	द्विपक्षीय गठजोड़, ऑकस (AUKUS), और क्वाड (QUAD) का सुदृढ़ीकरण[31]।	शंघाई सहयोग संगठन (SCO), द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी (रूस, पाकिस्तान)[6]।
2	आर्थिक और कनेक्टिविटी पहल	हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF), PGII ($६०० बिलियन), ग्लोबल गेटवे (EUR ३०० बिलियन)[4]।	बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (AIIB)[2]।
3	राजनयिक दृष्टिकोण	नियम-आधारित उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और लोकतान्त्रिक एकजुटता[2]।	वैश्विक सुरक्षा पहल (GSI) और बहुध्रुवीय व्यवस्था का कूटनीतिक प्रचार[2]।
4	सैन्य मुद्रा (Military Posture)	अपतटीय संतुलन (Offshore Balancing), नौवहन की स्वतंत्रता (FONOPs)[3]।	समुद्र नियंत्रण (Sea Control), एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल (A2/AD)[3]।

इस प्रकार दोनों शक्तियों के रणनीतिक हित परस्पर विरोधी हैं[3]। चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) को अमेरिका और उसके सहयोगी ऋण-जाल कूटनीति और क्षेत्रीय आधिपत्य स्थापित करने के साधन के रूप में देखते हैं, जबकि अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति को चीन "घेराव" (encirclement) की नीति के रूप में व्याख्यायित करता है[4]।

8.2. क्वाड (QUAD) का रणनीतिक विकासक्रम और कार्यप्रणाली

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) का विकासक्रम अत्यंत अनूठा और उतार-चढ़ाव से परिपूर्ण रहा है[7]। इसके ऐतिहासिक विकास को पांच प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

क्र	क्वाड का विकास चरण	कालखंड	मुख्य रणनीतिक विशेषताएं और संस्थागत उद्देश्य
1	आपदा प्रतिक्रिया समूह	२००४–२००५	हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) के लिए तदर्थ नौसैनिक समन्वय की स्थापना12।
2	क्वाड १.० (प्रारंभिक प्रयास)	२००७–२००८	शिंजो आबे द्वारा औपचारिक पहल; प्रथम अनौपचारिक बैठक; चीन के राजनयिक विरोध तथा ऑस्ट्रेलिया और भारत की कूटनीतिक हिचकिचाहट के कारण शीघ्र पतन6।

3	शीतकाल और निष्क्रियता	२००८–२०१६	समूह औपचारिक रूप से निष्क्रिय रहा, लेकिन द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय रणनीतिक गश्त और समुद्री सहयोग निरंतर जारी रहे11।
4	क्वाड २.० (पुनरुद्धार)	२०१७–२०२०	मनीला में पुनः स्थापना; चीनी आक्रामकता और गलवान गतिरोध के बाद रणनीतिक जुड़ाव में अभूतपूर्व तीव्रता6।
5	संस्थागत सुदृढ़ीकरण	२०२१–वर्तमान	राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर वार्षिक शिखर सम्मेलन; समुद्री डोमेन जागरूकता (IPMDA), साइबर सुरक्षा और लचीली आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण7।

क्वाड अपनी स्थापना से ही नाटो जैसे औपचारिक सैन्य संगठन के रूप में काम करने से बचता रहा है[11]। इसका रणनीतिक लचीलापन ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है[7]। जहां भारत अपनी गुटनिरपेक्ष परंपरा के कारण इसे एक विशिष्ट सैन्य गुट नहीं बनने देना चाहता, वहीं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके माध्यम से सैन्य अंतर-संचालन (interoperability) और कूटनीतिक संरेखण को सुदृढ़ कर रहे हैं[3]।

हाल के वर्षों में, क्वाड ने पारंपरिक सुरक्षा से आगे बढ़कर व्यावहारिक सहयोग के नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है[11]। इसमें समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) की शुरुआत की गई है, जो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को अंतरिक्ष-आधारित रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा प्रदान करती है ताकि वे अवैध रूप से मछली पकड़ने और समुद्री डकैती का मुकाबला कर सकें[36]। इसके अतिरिक्त, तकनीकी सुरक्षा के क्षेत्र में आपूर्ति शृंखला लचीलापन और महत्वपूर्ण खनिजों के सुरक्षित प्रवाह के लिए मई २०२६ में नई दिल्ली में २० बिलियन डॉलर की क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की घोषणा की गई है, जो इस मंच की बढ़ती आर्थिक परिपक्वता को दर्शाती है।

8.3. दक्षिण चीन सागर और ताइवान में चीनी ग्रे-जोन रणनीति एवं सुरक्षा खतरे

चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सीधे सैन्य संघर्ष से बचते हुए अपने दावों को मनवाने के लिए 'ग्रे-जोन' (grey-zone) रणनीति का सहारा ले रहा है[8]। यह रणनीति सैन्य बल प्रयोग की सीमा से ठीक नीचे रहकर मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की कला है[8]।

क्र	विवादित भौगोलिक क्षेत्र	चीनी सुरक्षा बलों की गतिविधियां (२०२५–२०२६)	अंतरराष्ट्रीय कानूनों/UNCLOS का उल्लंघन	क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य प्रभाव
1	प्रातस द्वीप (Pratas Island)	फरवरी २०२५ से मई २०२६ के मध्य चीनी जहाजों द्वारा ३९ बार घुसपैठ; टोही और खोजी ड्रोनों का निरंतर उपयोग।	ताइवान के घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) का प्रत्यक्ष उल्लंघन।	ताइवान की अग्रिम चौकियों और उसकी तटीय सुरक्षा बलों (CGA) पर भारी सैन्य दबाव।
2	स्कारबोरो रीफ (Scarborough Reef)	मार्च २०२६ में चीनी तटरक्षक बल (CCG) द्वारा "क्लियरिंग ऑपरेशन्स" के तहत फिलीपींस के जहाजों पर	२०१६ के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के फैसले और UNCLOS की संप्रभु सीमाओं की खुली अवहेलना।	फिलीपींस की समुद्री संप्रभुता को गंभीर आघात और मूंगा चट्टानों का विनाश9।

		बल प्रयोग।		
3	एंटेलोप रीफ (Antelope Reef)	परसेल द्वीप समूह में तीव्र गति से भूमि सुधार और सैन्य बुनियादी ढांचे (हेलीपैड, रडार स्टेशन) का निर्माण।	संप्रभुता के आधारहीन दावों के माध्यम से कृत्रिम संरचनाओं का अवैध निर्माण।	चीनी नौसेना (PLAN) की अग्रिम रसद क्षमता का विस्तार और लड़ाकू जहाजों का ठहराव।
4	विवादित भौगोलिक क्षेत्र	चीनी सुरक्षा बलों की गतिविधियां (२०२५–२०२६)	अंतरराष्ट्रीय कानूनों/UNCLOS का उल्लंघन	क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य प्रभाव

बीजिंग की इस आक्रामक रणनीति का विश्लेषण करने वाली सिंघुआ विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी सेंटर (ISSC) की '२०२६ एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिस्क फॉर चाइना' रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि चीनी नेतृत्व ताइवान जलडमरूमध्य में अमेरिकी हथियारों की बिक्री और जापान की बढ़ती भागीदारी को अपने लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता है[17]। इसके प्रत्युत्तर में चीनी सेना न केवल हवाई गश्त बढ़ा रही है बल्कि ताइवान के चारों ओर निरंतर नौसैनिक और कोस्ट गार्ड घेराबंदी का अभ्यास कर रही है।

चीनी नौसैनिक दबाव का मुकाबला करने के लिए ताइवान ने कड़े सुरक्षा उपाय अपनाए हैं[41]। जून २०२६ में ताइवान ने चीनी नौसैनिक संगरोध (blockade) का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर सिमुलेशन अभ्यास किया[41]। साथ ही, १ जुलाई २०२६ को ताइवान ने अपने नए लिटोरल कॉम्बैट कमांड (LCC) का गठन किया, जो स्वदेशी हिसउंग फेंग एंटी-शिप मिसाइलों और अमेरिकी मिसाइल प्रणालियों को एकीकृत कर २४ समुद्री मील की सीमा के भीतर तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है[41]।

8.4 भारतीय सुरक्षा वास्तुकला और रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा

भारत की हिंद-प्रशांत नीति कूटनीतिक रूप से अत्यंत सूक्ष्म और रणनीतिक रूप से संतुलित है[25]। भारत एक ओर जहाँ "नौवहन की स्वतंत्रता" (Freedom of Navigation) और वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था का खुलकर समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर वह अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र में विदेशी युद्धपोतों के प्रवेश पर पूर्व सूचना और अनुमति की नीति को लागू रखता है[23]। इस विरोधाभासी स्थिति के कारण अमेरिका द्वारा भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में 'नौवहन स्वतंत्रता संचालन' (FONOPs) के माध्यम से भारतीय दावों को समय-समय पर चुनौती दी जाती रही है[23]।

इसके बावजूद, चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण भारत ने अपनी पारंपरिक रक्षात्मक मुद्रा को बदलकर व्यावहारिक "क्षेत्रीय संतुलन" (Zone Balancing) की नीति अपनाई है[21]। इस सामरिक बदलाव को निम्नलिखित व्यावहारिक और बजटीय डेटा के माध्यम से समझा जा सकता है:

- रक्षा बजट आबंटन (२०२५): भारतीय नौसेना की तैनाती और आधुनिकीकरण के लिए बजट का विस्तार करते हुए इसे ५२,००० करोड़ रुपये तक पहुँचाया गया है, जिससे नए युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण तेज हो सके[21]।
- सीमा बुनियादी ढांचा विकास: २०२० के गतिरोध के बाद चीनी सीमा पर त्वरित सैन्य रसद सुनिश्चित करने के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) ने २०२४-२५ में १२५ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया है[21]।
- रणनीतिक सैन्य तैनाती: पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत ने ५०,००० से अधिक अतिरिक्त सैनिकों की स्थायी तैनाती सुनिश्चित की है[21]।
- रक्षा निर्यात संवर्धन: भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वर्ष २०२४-२५ में भारत का रक्षा निर्यात २१,००० करोड़ रुपये के

ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है[21]।

इसके अतिरिक्त, भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 'मालाबार नौसैनिक अभ्यास' के माध्यम से अपनी अंतर-संचालनीयता को अभूतपूर्व स्तर पर सुदृढ़ किया है[6]। हालाँकि, भारत यूरेशिया और हिंद-प्रशांत के बीच अपनी संतुलनकारी भूमिका के तहत क्वाड को एक औपचारिक सैन्य गठबंधन बनने से रोकता रहा है, ताकि वह मास्को के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बचाते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा कर सके[24]।

IX. निष्कर्ष

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जारी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल क्षेत्रीय नियंत्रण की जंग नहीं है, अपितु यह आने वाली सदी की वैश्विक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को परिभाषित करने का एक ऐतिहासिक द्वंद्व है[1]। चीनी आधिपत्य और उसकी 'ग्रे-जोन' आक्रामकता ने वैश्विक समुद्री नियमों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है[8]।

इस विषम वातावरण में क्वाड (QUAD) ने यह प्रमाणित किया है कि बिना किसी औपचारिक सैन्य संधि के भी, यह देशों की संप्रभुता की रक्षा करने, आर्थिक और तकनीकी लचीलापन सुनिश्चित करने और वास्तविक समय में समुद्री डेटा साझा करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है[7]। भारत के लिए, क्वाड का मंच चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है, बशर्ते भारत अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और बहु-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के लक्ष्यों के बीच आवश्यक सामंजस्य बनाए रखे[13]। अंततः, हिंद-प्रशांत की स्थिरता क्षेत्रीय लोकतंत्रों की रणनीतिक दूरदर्शिता और उनकी सामूहिक कूटनीतिक दृढ़ता पर निर्भर करेगी[32]।

संदर्भ सूची

[1] आब, शिंजो. (२००७). दो सागरों का मिलन. नई दिल्ली: भारतीय संसद का विशेष नीतिगत संबोधन[4]।

[2] ऐलिसन, ग्राहम. (२०१७). डेस्टिंड फॉर वॉर: कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप थ्यूसीडाइड्स ट्रैप?. न्यूयॉर्क: हॉटन मिफ्लिन हारकोर्ट[1]।

[3] फोंग, ब्रायन सी. एच. (२०२४). यूएस-चाइना राइवलरी: ग्रेट पावर कम्पटीशन इन द इंडो-पैसिफिक. एडिनबर्ग: एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस[3]।

[4] मोर्गेंथौ, हंस जे. (१९४८). पॉलिटिक्स अमंग नेशंस: द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस. न्यूयॉर्क: अल्फ्रेड ए. नॉप[22]।

[5] मोहन, सी. राजा. (२०१२). समुद्र मंथन: सिनो-इंडियन राइवलरी इन द इंडो-पैसिफिक. वाशिंगटन डीसी: कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस[27]।

[6] पंत, हर्ष वी. (२०२२). इंडिया एंड जापान: ए नेचुरल पार्टनरशिप इन द इंडो-पैसिफिक. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान[28]।

[7] राजगोपालन, राजेश. (२०२०). "इवेसिव बैलेंसिंग: इंडियाज अनवायबल इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजी." इंटरनेशनल अफेयर्स, ९६(१), ७५-९३[22]।

[8] वाल्ट्ज, केनेथ. (१९७९). थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. रीडिंग: एडिसन-वेस्ले[2]।

[9] सिंघुआ विश्वविद्यालय. (२०२६). २०२६ एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिस्क फॉर चाइना. बीजिंग: इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी सेंटर (ISSC)[17]।

[10] आर्य, ए. (2022). इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, राजस्थान विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस (वॉल्यूम 4, अंक 2, पृष्ठ 149–154)

[11] सी. राजा मोहन, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस।

[12] चीन को हर जगह खतरे दिखाई देते हैं। (2026, 7 जुलाई)। ANI न्यूज़।

[13] गो, आई., जैक्सन, एम., नागी, एस., एनजी, वी., फुमियो, ओ., सालेह, ए., योइचिरो, एस., और यामामोटो, आर. (2020). इंडो-पैसिफिक में समुद्री मुद्दे: "मुक्त और खुले" की साझा सोच बनाना। पैसिफिक फोरम, वॉल्यूम 20,

[14] इंडियाज़ वर्ल्ड। (2026a, 12 मार्च)। एशिया में शक्ति और व्यवस्था पर: प्रो. सी. राजा मोहन के साथ बातचीत। इंडियाज़ वर्ल्ड।

[15] इंडियाज़ वर्ल्ड। (2026b, 12 मार्च)। एशिया में शक्ति और व्यवस्था पर: प्रो. सी. राजा मोहन के साथ बातचीत। इंडियाज़ वर्ल्ड।

[16] इकबाल, एस., और खान, एम. ए. (2025, 28 नवंबर)। इंडो-पैसिफिक में अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता: यथार्थवाद और उदारवाद के नज़रिए का तुलनात्मक विश्लेषण।

[17] कुमार, ए. (2026)।, ताइवान के प्राटास द्वीपों पर चीन का 'ग्रे-ज़ोन' दबाव।

[18] LotusArise. (2023, 2 फरवरी), क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD) - UPSC।

[19] मोहन, सी. आर. (2017, 21 दिसंबर),यूरेशिया और इंडो-पैसिफिक के बीच: भारत की नई भू-राजनीति,कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस,

[20] नाथ, ई., और क्लिंगेबील, एस. (2023),इंडो-पैसिफिक में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: विकास सहयोग का प्रबंधन,IDOS पॉलिसी ब्रीफ में।

[21] गुयेन, टी. टी., इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन, वेस्ट एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज़, वियतनाम, खुराना, जी. एस., गांधी, पी., अन, पी. सी. एन., EFSAS, जैन, यू., बून, यू., अवदालियानी, ई., और जयशंकर, डी. (2024),भारत-प्रशांत रणनीति को आकार देना: चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) और भारत-जापान संबंध। अमेरिकन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (एआईजेबीएम) में (वॉल्यूम 07, अंक 09, पीपी. 01-07)

[22] ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन,(एन.डी.-ए). ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।

[23] ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन,(एन.डी.-बी). ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।

[24] ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन,(एन.डी.-सी). इंडो-पैसिफिक और क्वॉड ग्रुप: भारत की हिंद-प्रशांत नीति समावेशी, कितनी सफल

[25] पारुलेकर, एस. (2026ए, 16 अप्रैल),इंडो-पैसिफिक में चीन: जनवरी 2026,सीएनए।

[26] पारुलेकर, एस. (2026बी, 16 अप्रैल),इंडो-पैसिफिक में चीन: जनवरी 2026,एनसीसी।

[27] प्रोजेक्ट एमयूएसई--सत्यापन आवश्यक! (रा।)।

[28] सईद, एम. (2017ए),एशिया-पैसिफ़िक से इंडो-पैसिफ़िक तक: चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा,चाइना क्वार्टरली ऑफ़ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, 03(04), 499–512.

[29] सईद, एम. (2017b). एशिया-पैसिफ़िक से इंडो-पैसिफ़िक तक: चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा,चाइना क्वार्टरली ऑफ़ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, 03(04), 499–512.

[30] सरन, एस. (2024, 14 जून). क्वाड के दो दशक: इंडो-पैसिफ़िक में कूटनीति और सहयोग।

[31] सिंह, टी. पी. एस. और एल. जे. एस. और एन. के. (2024a). इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में भारत और क्वाड: समुद्री सुरक्षा पर एक नज़र।

[32] सिंह, टी. पी. एस. और एल. जे. एस. और एन. के. (2024b). इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में भारत और क्वाड: समुद्री सुरक्षा पर एक नज़र।

[33] स्मिथ, जे. एम., और स्मिथ, जे. एम. (2020). रणनीतिक स्वायत्तता और अमेरिका-भारत संबंध,वॉर ऑन द रॉक्स।